

RBI द्वारा NBFC एवं MFI ऋण पर जोखिमि भार में कमी करना

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था के खुदरा क्षेत्र को ऋण देने में वृद्धि करने के लिये [NBFC](#) और [सूक्ष्म वित्त संस्थानों](#) को दिये जाने वाले बैंक ऋणों के **जोखिमि भार** को कम कर दिया है।

ऋणों पर जोखिमि भार क्या है और इसका NBFC और बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- **परिचय:** जोखिमि भार एक प्रतशित कारक है जो बैंक की परसिंपत्तियों, जिसमें ऋण भी शामिल हैं, को सौंपा जाता है, ताकसिंभावति घाटे को कवर करने के लिये आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारति की जा सके।
 - उच्च जोखिमि भार से पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे ऋण महंगा हो जाता है, जबकि कम जोखिमि भार से पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे अधिक ऋण देना संभव हो जाता है।
- **मानदंड:** जोखिमि भार क्रेडिट रेटिंग, परसिंपत्त प्रकार और वनियिमों पर निर्भर करता है। उच्च रेटिंग वाले उधारकर्त्ताओं को नमिन जोखिमि भार मलिता है, जबकि नमिन रेटिंग वाले उधारकर्त्ताओं को उच्च जोखिमि भार का सामना करना पड़ता है।
- **कम जोखिमि भार का प्रभाव:**
 - NBFC को बैंक ऋण देने को प्रोत्साहति करना: बैंकों को ऋण के लिये कम पूंजी रखने की आवश्यकता है, जिससे NBFC को ऋण देने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी।
 - ऋण वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव: तरलता में वृद्धि से आवास, उपभोक्ता वित्त एवं MSMEs क्षेत्र में NBFC ऋण को बढ़ावा मलिता है। ऋण तक बेहतर पहुँच से खुदरा क्षेत्र को लाभ होता है।
 - वत्तितीय स्थरिता में वृद्धि: ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने से रोजगार, आय स्तर एवं वत्तितीय लचीलेपन में वृद्धि होती है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)

- **परिचय:** CAR, बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है जिससे बैंक के जोखिमि-भारति क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतशित के रूप में व्यक्त कया जाता है।
- **घटक:**
 - टयिर-1 पूंजी: मुख्य पूंजी (इक्विटी, शेयर पूंजी, रटिंड अर्नगि) का उपयोग बैंक के परचालन जारी रहने तक घाटे को वहन करने के लिये कया जाता है।
 - टयिर-2 पूंजी: द्वत्तीयक पूंजी (अनऑडिटिड रज़िर्व, अधीनस्थ ऋण) का उपयोग बैंक के बंद होने के समय कया जाता है।
- **वनियिमक आवश्यकता:** इसे [बेसल समझौते](#) द्वारा निर्धारति कया जाता है और केंद्रीय बैंकों (जैसे, भारत में RBI) द्वारा लागू कया जाता है।
 - बेसल III मानदंडों के अनुसार, बैंकों को वैश्वकि स्तर पर न्यूनतम 8% का CAR बनाए रखना आवश्यक होता है जबकि RBI ने भारतीय बैंकों के लिये इसे 9% अनविर्य कया है।
- **महत्त्व:** उच्च CAR यह दर्शाता है कि बैंक वत्तितीय रूप से स्थरि होने के साथ वत्तितीय संकटों से नपिटने में सक्षम है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)

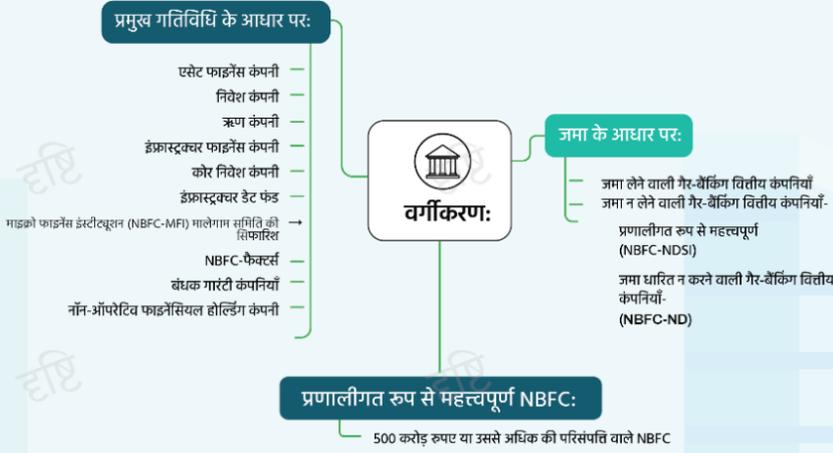
एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) ऋण प्रदान करती है, वित्तीय प्रतिभूतियाँ प्राप्त करती है, तथा पट्टे और बीमा सेवाएँ प्रदान करती है। हालाँकि, इसमें मुख्य रूप से कृषि, औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार या रियल एस्टेट में लगी कंपनियाँ शामिल नहीं होती हैं।

परिचय:

- बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है; भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है; चेक जारी नहीं कर सकती।
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा बीमा → NBFC जमाकर्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होता है।
- सार्वजनिक जमा 12 से 60 महीनों के लिये स्वीकार किये जा सकते हैं (कोई मांग जमा डिमांड डिपॉजिट नहीं)।
- NBFC को निवेश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता होती है।
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा बीमा → NBFC जमाकर्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होता है।
- प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएँ - व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, स्वर्ण ऋण, माइक्रोफाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, बीमा सेवाएँ, निवेश प्रबंधन।



वर्गीकरण:



विनियमन:

संस्था का प्रकार	नियामक प्राधिकरण
RBI के साथ पंजीकृत NBFC	राष्ट्रीय आवास बैंक
RBI के साथ पंजीकृत NBFC	राष्ट्रीय आवास बैंक
मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनियाँ, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियाँ, स्टॉक ब्रोकिंग, सामूहिक निवेश योजनाएँ (CIS)	सेबी
निधि कंपनियाँ, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियाँ	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)
चिट फंड कंपनियाँ	राज्य सरकार
बीमा कंपनी	IRDA
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियाँ	कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विनियमन पर्यवेक्षण और निगरानी। नियामक- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्रवर्तन एजेंसी- राज्य सरकारें

NBFC के लाभ:

- वित्तीय समावेशन
- नवोन्मेषी उत्पाद
- चलनिधि
- MSME के लिये सहयोगी

NBFC की चुनौतियाँ:

- वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ
- परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण जोखिम
- नियामक अनुपालन
- कॉर्पोरेट प्रशासन





सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI)

परिचय:

- वित्तीय सेवाएँ और छोटे मुद्रण के अग्र प्रदाता हैं।
- **लक्ष्य** - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को वित्त प्रदान करने, छोटे व्यवसाय और उद्योगों को
- अधिकतम वार्षिक आय मानदंड - 3 लाख रुपये (संवर्धित-छोटे क्षेत्रों में)

सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र का विकास

- **आरंभिक काल** (सन् 1974-1984):
 - पहिलियों के तहत श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना
 - गवर्नर ने SHG संरचना को बढ़ावा दिया
- **परिचरित अवधि** (सन् 2002-2006):
 - स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न अनुसंधित अग्र मानकों को सुदृढित करने के साथ-साथ विचार किया गया
 - SHG ने सूक्ष्म वित्त को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया
- **विकास और संरचना** (सन् 2007-2010):
 - **नियंत्रित वित्त** - सूक्ष्म वित्त संस्थानों का सौद विकास
 - **सहकारीकरण** - प्रत्येक राज्य में SHG का गठन
- **कृषि और पर्यावरण** (सन् 2010-2015):
 - **सहकारीकरण** (सन् 2010) ने विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता को
 - **NBFC की स्थापना** - केवल वित्त संस्थानों को सूक्ष्म वित्त संस्थान (NBFC-MFI)
 - **बैंक बैंक** (सर्वोच्च स्तर) को सहायता देने के साथ-साथ सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए
 - **सूक्ष्म वित्त** का प्रसारण (सन् 2015)



सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI) का विकास और प्रसारण के लिए विभिन्न योजनाएँ हैं।

विभिन्न संरचनाएँ



- **स्वयं सहायता समूह (SHG):**
 - औद्योगिक समूह (10-20 सदस्य) मिलकर कार्य करते हैं और अग्र प्रदाता करते हैं
 - SHG-के विकसित कार्यक्रम के माध्यम से बैंकों से ऋण प्राप्त करना
- **सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI):**
 - माइक्रो-क्रेडिट और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है
 - 4-10 सदस्यों वाले समूहों को सहायता देने के माध्यम से अग्र

MFI के प्रकार



- **NGO-MFI** (गैर-लाभकारी वित्त संस्थान) 1960 या भारतीय ट्रेड अधिनियम 1980 के तहत
- **सहकारी वित्त संस्थान**
- **आर-व** के अधिनियमों (संवर्धित अधिनियम, 2013 के अंतर्गत)
- **NBFC-MFI** (सूक्ष्म वित्त संस्थान का 80% हिस्सा)

लाभ

- विकसितकरण और वित्तीय समावेशन
- आर्थिक विकास (समृद्धि) और बेरोजगारी (समावेशन)
- संचय और संचयन (संचयन)
- महिला उद्योग



MFI की पूर्णविवरण	आगे की राह
उच्च स्तर पर	वित्तियोगिक निरीक्षण में सुधार करना और व्यापक दूर सेवा को बढ़ाना।
अग्र कार्यक्षेत्रों का अधिकार प्रदान करना	अग्र औद्योगिक प्रदान करने को सुदृढ करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
व्यापक वित्तियोगिक पर निरीक्षण	सहकारी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से वित्तियोगिक सेवाओं में वित्तियोगिक समावेशन।
अग्रकार्यक्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना	वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों/परियोजनाओं को बढ़ावा देना



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वार्षिक प्रश्न (PYQ)

????????????

Q. माइक्रोफाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें उपभोक्ता और स्वरोज़गार करने वाले दोनों शामिल हैं। माइक्रोफाइनेंस के तहत दी जाने वाली सेवा/सेवाएँ हैं (2011)

1. ऋण सुविधाएँ
2. बचत सुविधाएँ
3. बीमा सुविधाएँ
4. फंड ट्रांसफर सुविधाएँ

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

